भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **625**
उत्तर देने की तारीख **03** दिसम्बर**, 2025**

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति**,** 2025

625. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, अगली पीढ़ी की तकनीकों (5जी/6जी, उपग्रह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के लिए दिशा निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2025 को मंजूरी दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) महाराष्ट्र में सुदूर/आदिवासी जिले सहित उक्त नीति के तहत लाइसेंस के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनी परियोजनाओं और स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ है;

(ग) क्या जनजातीय/सुदूर क्षेत्रों में समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल कनेक्टिविटी (4जी/5जी/सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई-फाई) बढ़ाने के लिए कोई विशेष आवंटन या योजना निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछड़े जिलों में दूरसंचार और उपग्रह उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बनें;

(ङ) सरकार का राज्य-वार सेवाओं की शुरुआत, गुणवत्ता, सीमित सेवा उपलब्धता वाली बस्तियों और राशि के उपयोग को ट्रैक करने के लिए किस तरह के निगरानी तंत्र की स्थापना का विचार है; और

(च) इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान अनुमान जताया गया है कि अगले एक दशक में देश का दूरसंचार/डिजिटल क्षेत्र जीडीपी में कम से कम 20 प्रतिशत का योगदान देगा, इस संबंध में सरकार ने क्या समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (एनटीपी-25) वर्तमान में मसौदा तैयार किए जाने के चरण में है । एनटीपी-25 का उद्देश्य सेक्टर के लिए नीति और कार्यनीतिक दिशा तय करना है जिसके आधार पर भावी कार्य योजना बनाई जाएगी जिसमें राज्य या जिला स्तर पर प्राधिकार जारी करना, परियोजना को मंज़ूरी देना, आदि शामिल हो सकता है।

मसौदा एनटीपी-25 में सार्वभौमिक एवं सार्थक कनेक्टिविटी, घरेलू विनिर्माण, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आदि जैसे व्यापक नीतिगत विषयों को शामिल किया जाना अपेक्षित है।

एनटीपी-25 के नियमन की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सरकार दूरसंचार कनेक्टिविटी को लगातार सुदृढ़ कर रही है जिसमें डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे संशोधित भारतनेट कार्यक्रम, सेवा से वंचित गाँवों में 4जी सेचुरेशन, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, आदि परियोजनाओं के तहत दूरदराज़, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं। डीबीएन द्वारा वित्तपोषित विभिन्न स्कीमों के तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,156 गाँवों को कवर करने के लिए 2,644 टावर संस्थापित करने और सभी ग्राम पंचायतों को फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा, सरकार स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और स्थानीय मूल्य-संवर्धन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन स्कीम के माध्यम से दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है।

(च): वर्तमान में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 12–14% का योगदान देती है जिसके आने वाले दशक में लगभग 20% तक बढ़ने का अनुमान है जो आर्थिक विकास में दूरसंचार एवं डिजिटल सेक्टर की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह अनुमान विभिन्न वृहद आर्थिक कारकों जैसे वैश्विक आर्थिक रूझान, प्रौद्योगिकी अपनाने की साइकिल, निजी क्षेत्र के निवेश तथा अवसंरचना विकास पर निर्भर करता है।

*****